RAJYA SABHA

Thursday, the 10th *April*, 2003/20 *Chaitra*, 1925 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की सिफारिशें

*401. **श्री वशिष्ठ नारायण सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लंदन में आयोजित छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को पूर्णतया लागू कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले सम्मेलन के विचारार्थ विषय क्या होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, 14 से 18 सितम्बर, 1999 तक लंदन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों में शामिल थीं: महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय को हिन्दी शिक्षण के एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, भारत और मॉरीशस सरकारों को मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए; संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे मिशनों/केन्द्रों को भारतीय मूल के लोगों के साथ सम्पर्क बनाना चाहिए ताकि उनके प्रत्यायन के देशों में हिंदी के अध्ययन को संवर्द्धित किया जा सके और आवश्यकतानुसार उन्हें हिंदी पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। हिंदी अध्ययन को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के द्वारा सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।

सरकार ने सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए हर प्रयास किए हैं। महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है और यह हिंदी अध्ययन के लिए यह एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। भारत और मॉरीशस के बीच समझौता-ज्ञापन के सम्पन्न होने के बाद सचिवालय की स्थापना के लिए मॉरीशस की नेशनल असेम्बली ने 16 नवम्बर, 2002 को एक विधेयक पारित किया। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को एक राजभाषा के रूप में स्थापित करने के विषय पर विदेश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। हमारे मिशन/केन्द्र अपने प्रत्यायन के देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को समर्थन और संवर्द्धन करने की दृष्टि से हिंदी विद्वानों/संगठनों के साथ निकट सम्पर्क में रहते हैं। उनकी मांग के अनुसार मंत्रालय द्वारा उन्हें हिंदी सीखने की सामग्री, पुस्तकें, सी डी, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हिंदी सिखाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सी-डैक, पुणे द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे, लीला प्रबोध और प्रवीण विकसित किए गए हैं और हिंदी सीखने के लिए इनका भी उपयोग किया जा रहा है।

सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून, 2003 तक पारामारिबो (सूरीनाम) में आयोजित किया जा रहा है। सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन की विषय वस्तु है: "विश्व हिंदी: नई शताब्दी की चुनौतियां"। विदेशियों, विशेष रूप से भारतीय मूल के लोगों में हिंदी के प्रयोग के तरीकों और साधनों को लोकप्रिय बनाने, आधुनिक तरीकों और सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति द्वारा हिंदी सीखने को सुविधाजनक बनाने और हिंदी भाषा तथा साहित्य की समृद्ध विरासत के बारे में बेहतर जानकारी देने पर बल दिया जाएगा।

Recommendations of sixth World Hindi Conference

†*401. SHRI BASHISTHA NARAIN SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the recommendation of the Sixth World Hindi Conference organised in London;

(b) whether these recommendations have been implemented fully, if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) What would be the terms of reference of the next conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (d) The VI World Hindi Conference was organised at London from 14th to 18th September, 1999. The major recommendations of the Conference included, that Mahatma Gandhi International Hindi University should be developed as an international centre of Hindi learning. The Governments of India and Mauritius should expedite the process of establishment of World Hindi Secretariat in Mauritius. Serious efforts should be made towards recognition of Hindi as one of the official languages in the UN. Our Missions/Posts should liaise with the people of Indian origin so that teaching of Hindi is promoted in the countries of their accreditation and Hindi books and other teaching material should be provided to them as required. Hindi learning should be facilitated with the use of the advancement of information technology.

The Government made every effort to implement the recommendations. The Mahatma Gandhi International Hindi University has been established and is functioning as an international centre of Hindi learing. After a Memorandum of Understanding having been signed between India and Mauritius, the Mauritian National Assembly has passed a Bill on 16th November, 2002 for setting up of the Secretariat. A high-level Committee has also been set up under the chairmanship of External Affairs. Minister on the subject of recognising Hindi as one of the Official Languages in the UN. Our Missions/Posts are maintaining close liaison with the Hindi scholars/ organisations in the countries of their accreditation with a view to support and enrich their Hindi propagating activities. Hindi learning material, books, CDs, software are being catered to them by the Ministry, as per their demands. Different software to facilitate Hindi teaching have been developed by C-DAC, Pune, such as, LILA PRABODH and PRAVEEN and these are also being used for Hindi learning.

The VII World Hindi Conference is being organised at Paramaribo (Surinam) from 5th to 9th June, 2003. "World Hindi - Challenges of the new Century" is the theme of the VII World Hindi Conference. Emphasis will be on exploring the ways and means of popularising the use of Hindi among foreigners, particularly people of Indian origin, facilitating the learning of Hindi using modern methods and

advancement of information technology and create better awareness of the rich legacy of Hindi language and literature.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: सभापति महोदय, जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें दो पूरक प्रश्न मुझे पूछने हैं। पहला, उस समय छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को मान्यता दिलाए जाने की बात थी, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है इसकी जानकारी मैं चाहता हूं?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिनदी भाषा को कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज़ बनाया जाए, तो एक तो मैं इस सदन में यह जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपना भाषण हिन्दी में किया था। दूसरा, वहां पर हिन्दी को ऑफिशियल लैंग्वेज़ बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये के खर्च का इंतजाम हम लोगों को करना है। भारत के प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को कहा है कि इसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा वह हम देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए कुछ और देशों की मदद की भी जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जो रेकरिंग खर्च होता है, जो लगातार आने वाले वर्षों में खर्चा होगा उस पैसे का इंतजाम भी सारे देशों को जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा, तो इस दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जल्दी ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: सभापति महोदय, छठा विश्व हिन्दी सम्मेलन जब हुआ तो उसके संचालन के संबंध में, प्रतिनिधियों के चयन के संबंध में और जो सामग्रियां प्रकाशित होने वाली थीं उसके संबंध में कई लेख समाचार-पत्रों में आए। उस छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन के दरम्यान जो त्रुटियां देखी गईं, उन त्रुटियों से मुक्ति पाने के लिए क्या इस बार विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था या कुछ विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में जो त्रुटियों की जानकारी हमें मिली है, वे त्रुटियां सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में न रहें इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा और अखबार के माध्यम से जिस समाचार का हवाला अभी माननीय सदस्य ने दिया है, यह अच्छा है कि जो त्रुटि है उसके बारे में, अखबार वालों ने लिखा है और सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हम उन सारी कमियों को पूरा करेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या हमारी सरकार इस बात को जानती है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार और हिन्दी का जो

वाजिब देय है उस देय को दिलाने के प्रति हमारी सरकार कितनी गंभीर है और अगर गंभीर होती तो पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन से लेकर छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन तक एक ही मांग को बार-बार क्यों दोहराया जाता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिलाया जाएगा? माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री वहां हिन्दी में बोले और प्रधान मंत्री जी यह भी कहते हैं कि विदेश में हिन्दी में बोलना आसान होता है और देश में हिन्दी बोलना मुश्किल होता है। सभापति जी, पहले सम्मेलन से लेकर छठे सम्मेलन तक और यह जो हिन्दी सम्मेलन आप कर रहे हैं, ये हिन्दी सम्मेलन नहीं बल्कि इन्होंने हिन्दी मेलों का रूप ले लिया है, हिन्दी जमावड़ों का रूप ले लिया है और हिन्दी के कई प्रतिनिधि साहित्यकार, प्रतिनिधि संस्थाएं वहां प्रतिनिधित्व नहीं पातीं। इसलिए मेरा पहला सवाल तो यह है कि सम्मेलन के मायने क्या होते हैं? आप अगर पिछले, छठे सम्मेलन में का विषय देखें तो वह "हिन्दी के सामने भावी चुनौतियां" विषय था और अब सातवें सम्मेलन में भी अप्रत्यक्ष रूप से वही विषय है, लेकिन उस सम्मेलन में भी उस विषय पर कोई खास चर्चा नहीं हुई, हिन्दी के साहित्यकार वहां पहुंच ही नहीं पाए जबकि दुनियाभर के प्रतिनिधि जुटा लिए गए। तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने के लिए आप कोई एक स्थाई समिति नियोजित करेंगे ताकि वह हिंदी सम्मेलन के आयोजनों का पूरा भार ले? दूसरा, मेरा कहना यह है कि आप यह सम्मेलन कर रहे हैं। पहला सम्मेलन हुआ, दूसरा सम्मेलन हुआ और दूसरे व तीसरे सम्मेलन के बीच में 7 साल का अंतराल है। अब तीसरे और चौथे सम्मेलन के बीच में 10 साल का अंतराल है जैसाकि सम्मेलन के प्रति हमारी अपनी कोई दायबद्धता नहीं, प्रतिबद्धता नहीं है। अगर प्रतिबद्धता होती तो आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, हम ने अभी स्वर्ण जयंती भी मना ली, लेकिन हिंदी को वह वाजिब हक नहीं मिला। सभापति जी, हिंदी को जब तक हमारे मंत्रालयों में उचित स्थान नहीं मिलता तब तक इसका प्रसार नहीं होगा क्योंकि हमारे मंत्रालयों में ही हिंदी की स्थिति सबसे खराब है। इसलिए हमारे मंत्रालयों में हिंदी की स्थिति सुधारने के लिए और हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए यह बहुत आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश का परिचय सिर्फ उसका भूगोल नहीं होता बल्कि उसकी संस्कृति होती है जिसका बहुत बड़ा संबंध उस देश की भाषा से होता है। महोदय, अभी "यूनीसेफ" ने अपने एक अध्ययन में बताया है कि तीन हजार भाषाएं लुप्तप्राय: होने को हैं और आज वैश्वीकरण के युग में कहीं हिंदी का लोप न हो जाय, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं क्योंकि खाली यह कहकर कि प्रधान मंत्री जी ने यूएन०ओ० में हिंदी में भाषण दिया और औपचारिकता पूरी हो गयी, यह ठीक नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, सरला जी हिंदी की खुद बहुत अच्छी जानकार और विद्वान हैं, इसलिए उन्होंने जो भी चिंता व्यक्त की है, उससे हमारी कोई

असहमति नहीं है। राजभाषा होने के नाते हिंदी का प्रचार-प्रसार ज्यादा-से-ज्यादा हो सके, उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। अब जहां तक आपने सवाल पूछा है कि इसका कोई पर्मानेंट सेक्रेटेरिएट बनाने का इरादा है या नहीं, हम आपकी जानकारी और आप के माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहेंगे कि छठे विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद एक सेक्रेटेरिएट बनाने का विचार उस प्रस्ताव में आया था जिस पर भारत की सरकार मॉरीशस के साथ मिलकर काम कर रही है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, पहले सम्मेलन में भी यह प्रस्ताव था ... **(व्यवधान)**..

श्री दिग्विजय सिंह: अब उत्तर तो आप सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**.. हम इतिहास की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह: आप सुनेंगी? यही तो आप के साथ परेशानी है। मैं कह रहा हूं कि आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं अपने को उससे सहमत मानता हूं। मैं भी आपकी चिंता में शामिल हूं। सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि सरकार ने क्या किया है। इसलिए हमने मॉरीशस में हिंदी सेक्रेटेरिएट बनाने का काम प्रारंभ किया है। भारत की तरफ से भारत के शिक्षा मंत्री डा॰ मुरली मनोहर जोशी ने उसका शिलान्यास किया है और मॉरीशस की संसद में 16 सितंबर को वह बिल पास हुआ है। इस तरह भारत सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम कह चुके हैं कि उस सेक्रेटेरिएट के बनाने में जो भी खर्चा आएगा, उस सेक्रेटेरिएट का वहन हम करेंगे। इसलिए हमारी तरफ से कोई कमी होने वाली नहीं है। महोदय, मैं सरला जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कम-से-कम हम लोग जब तक हैं तब तक आप इसकी चिंता न करें।

श्री सभापति: वह सेक्रेटेरिएट के बारे में कह रही थीं, वहां काम हिंदी में होगा या नहीं होगा?

श्री दिग्विजय सिंह: जी, वहीं तो मैं कह रहा हूं कि इसको मॉनीटर करने के लिए, उसका सेक्रेटेरिएट वहां बनाया जाएगा। उसका सेक्रेटरी जनरल मॉरीशस की सरकार तय करेगी, डिप्टी-सेक्रेटरी जनरल हमारा होगा। जहां तक और मंत्रालयों में कामकाज का सवाल है...

श्री जनेश्वर मिश्र: वहां कामकाज हिंदी में होगा कि नहीं?

श्री दिग्विजय सिंह: हिंदी में होगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, मॉरीशस की सरकार ने कहा है कि हम खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्रीमती गुरचरण कौर।

श्रीमती गुरचरण कौर: धन्यवाद, महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विदेशों में भारतीय मूल के लोगों से सम्पर्क किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि कितने देशों में भारतीय मूल के लोगों से सम्पर्क किया गया है और उन की वैसी मानसिकता बनाने के लिए आप ने कौन-कौन से साधन अपनाए हैं? महोदय, हम अपने देश में रहते हुए लोगों में हिंदी के प्रति प्यार पैदा नहीं करते और जब हम मंत्रालय में जाते हैं तो वहां के लोग अंग्रेजी में बोलने में अपना गौरव समझते हैं। अगर वे हिंदी के दो शब्द बोलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि वे हीनता की भावना को महसूस कर रहे हैं। यह बड़े दु:ख की बात है। महोदय, मैं उन से यह भी जानना चाहूंगी कि उन की इस मानसिकता को बदलने कि लिए आप कौन-कौन से उपाय कर रहे हैं ताकि हमारे लोग अपनी संस्कृति से दूर न जाएं।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने अपना सवाल दो भागों में पूछा है, जिसमें एक भाग का रिश्ता तो हमसे है और दूसरे भाग का रिश्ता हमसे नहीं है। जिस भाग का रिश्ता हमसे है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि दुनिया में तकरीबन बीस ऐसे देश हैं, जहां पर हिंदी को प्राथमिकता से देखा जा सकता है और भारत की सरकार उसका प्रयास कर रही है। उसी प्रयास में अभी कुछ दिनों पहले, जनवरी महीने में हमारे यहां आप्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन किया गया था और उसमें इन बातों को चिह्नित किया गया था। तो भारत सरकार इस दिशा में जो प्रयास कर सकती है वह प्रयास जारी हैं।

श्री सभापति: नेक्सट क्वैश्चन।

श्री दत्ता मेघे: सर, बहुत इम्पोर्टेण्ट सवाल है।

श्री सभापति: इम्पोर्टेण्ट है, लेकिन बाकी के भी सब इम्पोर्टेण्ट हैं।

प्रो॰ रामदेव भंडारी: सर, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हिंदी की जो उपेक्षा होती रही है।

श्री सभापति: नहीं। सरला जी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं समझता हूं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: कृपा करके एलाऊ करें, सर।

श्री सभापति: कृपा करने की जरूरत नहीं है। आप बोलना चाहें तो मैं इजाजत दे दूंगा, लेकिन सरला जी बहुत कुछ कह चुकी हैं और जवाब भी अच्छी तरह से मिल गया है।

श्री दत्ता मेघे: सर, वर्धा के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। यह वर्धा के बारे में नहीं है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मेरा एक ही सवाल है।

श्री सभापति: ठीक है, आप कर लीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सभापति जी, हमारे जो राजदूत हैं विदेशों में, वे वहां किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? वहां हिंदी का प्रयोग होता है या नहीं होता है? मैं यह विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्योंकि मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से वहां बिल्कुल हिंदी का प्रयोग नहीं होता, जो हमारे राजदूत हैं वे हिंदी का प्रयोग नहीं करते।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है कि हिंदी को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए राजभाषा के रूप में, वह विदेश में तो क्या देश में भी नहीं मिल रही है। इसके लिए पूरा सदन चिंतित है और इसलिए हम भंडारी जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जो राजदूत हैं उनका प्रयास होता है कि वे हिंदी का भी उपयोग कर सकें, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरी है क्योंकि जो माहौल है और जिस माहौल में वे काम कर रहे हैं। हमारे यहां राजदूत रहे डा॰ कर्ण सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जितना वहां जाकर हिंदी में काम किया है, उतना किसी ने नहीं किया होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आदमी-आदमी पर भी यह निर्भर करता है, लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से यह प्रयास होता है कि भारतीय भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो।

Amendment of Central Motor Vehicles rules

*402. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government are proposing to amend the Central Motor Vehicles rules again to facilitate alternative technology without the safeguards prescribed by the Apex Committee;

(b) whether Government intend to introduce a monopoly of foreign technology in the transport sector; and

(c) if not, what effective steps are being taken to prevent the State Governments from introducing the monopoly technology?